

स्टार्टअप इकोसिस्टम का वसितार

यह संपादकीय 05/12/2024 को द हट्टि बज़िनेस लाइन में प्रकाशित "UAE galvanising start-ups" पर आधारित है। इस लेख में स्टार्टअप इकोसिस्टम के वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरते भारत की छवि प्रस्तुत की गई है, जिसमें 140,000 से अधिक स्टार्टअप और 111 यूनिफ़ॉर्म हैं, जिनमें UAE के 20 बिलियन डॉलर के निवेश से समर्थन मिला है। हालाँकि, इस लेख में विकास को बनाए रखने के लिये फंडिंग, वनियमन और नवाचार में चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

प्रलिस के लिये:

[भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम](#), [स्टार्टअप इंडिया](#), [सर्टिडअप इंडिया](#), [फास्ट मूविंग कंज़युमर गुड्स \(FMCG\)](#), [आर्टफिशियल इंटेलिजेंस](#), [भारतीय रज़िर्व बैंक](#), [कॉरपोरेट वेंचर कैपिटल](#), [अटल इनोवेशन मशिन](#), [स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स](#), [नेशनल रसिर्च फाउंडेशन](#), [उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि \(SAMRIDH\) कार्यक्रम के लिये MeitY के स्टार्टअप एक्सेलेरेटरस](#)

मेन्स के लिये:

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के वर्तमान विकास चालक, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है, जिसमें 140,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 111 यूनिफ़ॉर्म विविध क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। UAE एक महत्त्वपूर्ण सामरिक साझेदार बन गया है, जिसमें 20 बिलियन डॉलर से अधिक का महत्त्वपूर्ण निवेश है और अंतरराष्ट्रीय वसितार की तलाश कर रहे भारतीय उद्यमियों को महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है। दुबई के 30% से अधिक स्टार्टअप भारतीयों द्वारा स्थापित किये गए हैं, जो दोनों देशों के बीच गहन उद्यमशीलता तालमेल को दर्शाता है। हालाँकि, भारत को अपनी स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ाने, फंडिंग, वनियामक ढाँचे व अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिये नरितर नवाचार में चुनौतियों का समाधान करने के लिये और अधिक काम करने की आवश्यकता है।

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के वर्तमान विकास चालक क्या हैं?

- सरकारी पहल और नीतितगत समर्थन: भारत सरकार ने [स्टार्टअप इंडिया](#), [सर्टिडअप इंडिया](#) जैसी नीतियों को लागू किया है, कर छूट, वतित पोषण और इनक्यूबेटर्स के लिये समर्थन की पेशकश की है, जिससे उद्यमशीलता गतिविधि को काफी बढ़ावा मिला है।
 - जून 2023 तक, इस पहल के तहत 100,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है, जो इसके व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।
- डिजिटल अवसंरचना का वसितार: स्मार्टफोन और कफायती इंटरनेट के प्रसार ने डिजिटल अभिगम का वसितार किया है, जिससे स्टार्टअप को व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँचने में मदद मिली है।
 - मूल उपकरण निर्माताओं और मूल डिज़ाइन से भारी निवेश के कारण भारत अब मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निरिमाण केंद्र है।
 - इसके अलावा, भारत में वर्तमान में 820 मिलियन से अधिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो डिजिटल व्यवसायों के विकास में सहायक हैं।
- बढ़ता निवेश पारिस्थितिकी तंत्र: उद्यम पूंजी और नज़ी इक्विटी निवेश में वृद्धि ने स्टार्टअप को आवश्यक वतितपोषण उपलब्ध कराया है।
 - वर्ष 2014 से 2024 की पहली छमाही के दौरान, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने 150 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित किया, जिसमें [ई-कॉमर्स](#), [फिनिटेक](#) और [एंटरप्राइज टेक](#) सबसे आगे रहे, जिनोंने कुल फंडिंग में 52% का योगदान दिया।
 - गूगल के लॉन्चपैड और माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम वतितपोषण, मार्गदर्शन एवं बाज़ार अभिगम प्रदान करते हैं।
- विकासशील उपभोक्ता बाज़ार: बढ़ती प्रयोज्य आय के साथ बढ़ते मध्यम वर्ग ने नए उत्पादों और सेवाओं के लिये एक सुदृढ़ घरेलू बाज़ार का निर्माण किया है।
 - भारत के [फास्ट मूविंग कंज़युमर गुड्स \(FMCG\)](#) क्षेत्र में जुलाई-सितंबर 2024 में ग्रामीण मांग के कारण मूल्य के हिसाब से 5.7% और मात्रा के हिसाब से 4.1% की वृद्धि हुई।
 - अनुमानों से पता चलता है कि भारत का समृद्ध वर्ग वर्ष 2027 तक 100 मिलियन तक पहुँच जाएगा, जिससे स्टार्टअप के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे।
- सहायक वनियामक वातावरण: हाल ही में किये गए वनियामक सुधारों ने व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित किया है। [भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) ने अपनी भारतीय सहायक कंपनियों के साथ 'रिवर्स फ्लपि' वलिय से गुजरने वाली वदेशी कंपनियों के लिये अनुपालन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित

किया है, जिससे समयसीमा 12-18 महीने से घटकर केवल 3-4 महीने रह गई है।

◦ इस कदम से कार्यकुशलता बढ़ेगी और स्टार्टअप्स को भारत में सूचीबद्ध होने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

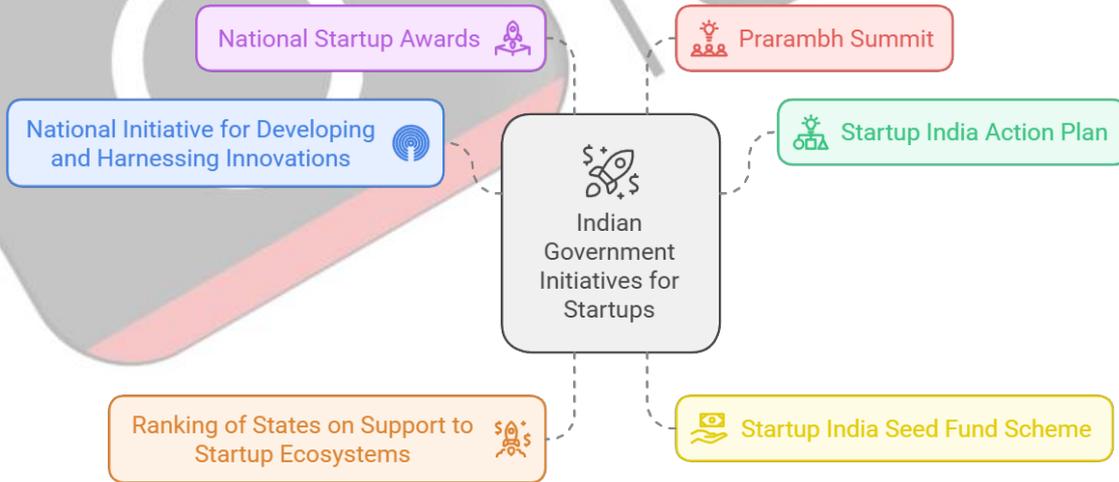
- **बढ़ते इनक्यूबेशन और त्वरण कार्यक्रम:** IIM बैंगलोर के NSRCEL जैसे संस्थान मार्गदर्शन, वित्त पोषण और संसाधन उपलब्ध कराते हैं, प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप का पोषण करते हैं तथा नवाचार को बढ़ावा देते हैं।
 - **महिला उद्यमिता कार्यक्रम** जैसे कार्यक्रम गोताखोरी को समर्थन देने में सहायक रहे हैं
- **डीप-टेक और AI स्टार्टअप्स का उदय:** **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और IoT** जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की मांग डीप-टेक स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा दे रही है।
 - बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की रिपोर्ट के अनुसार, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की तैयारी** में भारत शीर्ष दावेदार के रूप में उभरा है, तथा **वैश्व स्तर पर शीर्ष 10 देशों में शामिल है।**
 - नैसकॉम के अनुसार, भारत का डीपटेक क्षेत्र में 3,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और **पछिले एक दशक में इसकी वृद्धि दर 53%** रही है।
- **D2C (डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर) मॉडल का वसितार:** डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर मॉडल ने गति पकड़ी है, जिसमें स्टार्टअप्स बचौलियों को दरकिनार कर डिजिटल रूप से उपभोक्ताओं से जुड़ रहे हैं।
 - भारतीय **D2C बाजार के वर्ष 2025 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद** है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और व्यक्तिगत मार्केटिंग टूल को अपनाने से यह प्रवृत्ति बढ़ रही है।
- **टयिर-2 और टयिर-3 शहरों में उद्यमिता का उदय:** उद्यमिता अब केवल महानगरों तक सीमिति नहीं रह गई है; छोटे शहर भी स्टार्टअप केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।
 - **अटल इनोवेशन मिशन** जैसी पहल इनक्यूबेटर और फंडिंग के माध्यम से टयिर-2 और टयिर-3 शहरों में उद्यमियों को सक्रिय बना रही है।
 - **वर्ष 2023 में DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 50% से अधिक स्टार्टअप** गैर-मेट्रो क्षेत्रों से उत्पन्न होंगे, जो इस विकेंद्रीकृत विकास को प्रदर्शित करता है।
- **डिजिटल भुगतान क्रांति और फिनटेक बूम:** UPI के अंगीकरण और डिजिटल भुगतान के विकास ने फिनटेक परदृश्य को बदल दिया है, जिससे स्टार्टअप्स के लिये अवसर उत्पन्न हुए हैं।
 - अकेले अक्टूबर 2023 में 1.1 बिलियन से अधिक **UPI लेनदेन** किये गए, जिससे फोनपे और रेज़रपे जैसे स्टार्टअप को तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद मिली।
 - वैश्विक स्तर पर फिनटेक हब के रूप में प्रचारित भारतीय **फिनटेक बाजार** का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इसकी प्रबंधनाधीन परसिपततियाँ (AUM) **1 ट्रिलियन डॉलर तक** पहुँच जाएगी, जो वर्ष 2021 के इसके लगभग 100 बिलियन डॉलर के आकार से 10 गुना अधिक है।
- **स्थिरता और हरति स्टार्टअप को बढ़ावा देना:** भारत के **नेट जीरो एमिशन टारगेट- 2070** जैसी सरकारी परतबिद्धताओं से स्थिरता-केंद्रित स्टार्टअप लोकप्रिय हो रहे हैं।
 - **इलेक्ट्रिकिपे और ज़पि इलेक्ट्रिकि** जैसे स्टार्टअप EV और स्वच्छ ऊर्जा बाजारों का लाभ उठा रहे हैं। **भारत में UNDP एक्सेलेरेटर लैब्स** ने हरति नवाचार को और बढ़ावा दिया है।
- **कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल (CVC) का उदय:** बड़ी कंपनियाँ **कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल** के माध्यम से स्टार्टअप्स में नविश कर रही हैं, न केवल वित्तपोषण की पेशकश कर रही हैं, बल्कि बाजार विशेषज्ञता भी प्रदान कर रही हैं।
 - **रलायंस, टाटा और इंफोसिस** जैसी कंपनियों के पास सक्रिय CVC शाखाएँ हैं। यह एकीकरण स्टार्टअप्स को वसितार और नवाचार के लिये संसाधन प्रदान करता है।
- **उद्यमिता की ओर सांस्कृतिक बदलाव:** भारत में बढ़ते सांस्कृतिक बदलाव के तहत **स्टार्टअप को आकांक्षापूर्ण करियर विकल्प के रूप में देखा** जा रहा है, जिसमें जोखिम उठाना सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य होता जा रहा है।
 - **शार्क टैंक इंडिया** जैसे मीडिया कार्यक्रमों और स्टार्टअप की सफलता की कहानियों ने उद्यमशीलता को लोकप्रिय बनाया है।
 - सर्वेक्षणों से पता चलता है कि **77% भारतीय युवाओं ने अपना स्वयं का उद्यम शुरू करने में रुचि व्यक्त की।**

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **चलनधि और वित्तपोषण की चुनौतियों में कमी:** भारत के स्टार्टअप पारसिथितिकी तंत्र को वित्तपोषण में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर सत्रक नविश प्रथाओं की ओर बदलाव को दर्शाता है।
 - नविशकों में जोखिम लेने की क्षमता कम होने के कारण वे विकास की तुलना में लाभप्रदता को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स को वसितार के लिये बाह्य पूंजी पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
 - भारतीय स्टार्टअप्स ने **वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में फंडिंग में लगभग 73% की गरिबट दर** की है, बढ़ती परचालन लागत के बीच स्टार्टअप स्थिरता से जूझ रहे हैं।
- **नीतगित असंथरिता और करराधान संबंधी समस्यारूपें:** करराधान नीतियों में लगातार परविरतन और नयियामक असस्पष्टता नविशकों के वशिवास तथा स्टार्टअप्स के लिये परचालन संबंधी सुवधि को कमज़ोर करती है।
 - **वर्ष 2023 में वदिशी नविशकों पर एंजल टैक्स** लगाने का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाना है, लेकिन इससे शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स में वैध वदिशी नविश में बाधा उत्पन्न होगी।
 - **स्टार्टअप इंडिया** जैसी पहल के बावजूद, अधिकांश भारतीय स्टार्टअप अभी भी अपने संसाधनों का एक बड़ा हिससा अनुपालन पर खर्च करते हैं, जिससे **नवाचार पर उनका ध्यान सीमिति** हो जाता है।
- **प्रतभिा परतधारण और कौशल असंतुलन:** जबकि भारत परतविरष बड़ी संख्या में कुशल **सनातक तैयार** करता है, स्टार्टअप्स को वैश्विक अवसरों और घरेलू वेतन असमानताओं के कारण शीर्ष परतभिाओं को बनाए रखने में कठनिाइयों का सामना करना पड़ता है।
 - वदिश में या स्थापति बहुराष्ट्रीय कंपनियों में स्थायी नौकरियों के आकर्षण ने AI व मशीन लर्निंग जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में **परतभिा पलायन** को और बदतर बना दिया है।

- वर्ष 2015 और 2022 के दौरान 1.3 मिलियन भारतीयों ने देश छोड़ दिया, जिनमें से कई उच्च शक्ति पेशेवर थे, जिससे नवाचार करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिये प्रतिभा की कमी उत्पन्न हो गई।
- **शहरी बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता:** स्टार्टअप मुख्यतः शहर-केंद्रित व्यवसाय मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा ग्रामीण भारत की विशाल संभावनाओं की उपेक्षा करते हैं।
 - यह अतिनिर्भरता उनकी स्केलेबिलिटी को सीमित करती है और भारत की 65% से अधिक आबादी वाले बाजार से चूक जाती है तथा स्टार्टअप अभी भी रसद एवं बुनियादी अवसंरचना की चुनौतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिये संघर्ष करते हैं।
- **प्रमुख क्षेत्रों में बाजार संतृप्त और वखंडन:** कुछ उद्योग, जैसे एडटेक और फिनिटेक, संतृप्त बटु पर पहुँच रहे हैं, जिससे तीव्र प्रतिस्पर्धा एवं घटते मार्जिन हो रहे हैं।
 - प्रमुख अभिकर्ताओं का पतन यह दर्शाता है कि किस प्रकार अतिविस्तार और अनियमित प्रतिस्पर्धा ने इन क्षेत्रों को अस्थिर कर दिया है।
 - इस संतृप्त के परिणामस्वरूप छूटनी और वित्त पोषण में कमी आई है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ा है।
- **शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप के बीच अपर्याप्त सहयोग:** भारत के शैक्षणिक संस्थान स्टार्टअप के लिये नवाचार के इंजन के रूप में अभी भी कम उपयोग में हैं।
 - सलिकॉन वैली के विपरीत, जहाँ शिक्षा व्यावसायीकरण को बढ़ावा देती है, भारतीय स्टार्टअप शायद ही कभी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिये अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करते हैं।
 - वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत भर के 500 औद्योगिक समूहों में से 30-35% के आसपास कोई शोध संस्थान या विश्वविद्यालय नहीं है।
- **डिजिटल डिविड और बुनियादी अवसंरचना का अंतर:** डिजिटल उपकरणों के प्रसार के बावजूद, स्टार्टअप को असंगत बुनियादी अवसंरचना के कारण बाधा आ रही है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
 - ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट की अनुपस्थिति अप्रयुक्त बाजारों तक पहुँच को सीमित करती है, जिससे कृषि प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों का विकास धीमा हो जाता है।
 - वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि लगभग 60% ग्रामीण आबादी अभी भी सक्रिय रूप से इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रही है, स्टार्टअप वंचित आबादी को स्केलेबल, तकनीक-संचालित समाधान देने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
- **संधारणीयता और ESG संरक्षण पर ध्यान का अभाव:** पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों के साथ संरेखित करने में विफल रहने के कारण स्टार्टअप की लगातार जाँच की जा रही है, जिससे प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम एवं नयामक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
 - स्वर्गी और ज़ोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफॉर्मों को प्लास्टिक पर अत्यधिक निर्भरता के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा।
 - चूँकि भारत एक चक्रीय अर्थव्यवस्था और नेट-शून्य प्रतिबद्धताओं पर जोर दे रहा है, इसलिये संधारणीय प्रथाओं को अपनाने में विफल रहने वाले स्टार्टअप के लिये बाजार का विश्वास एवं वित्तपोषण खोने का जोखिम है।
- **बढ़ता संरक्षणवाद और वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** भारत के स्टार्टअप को फिनिटेक, गेमिंग और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ अंतरराष्ट्रीय अभिकर्ता हावी हैं।
 - साथ ही, स्थानीय संरक्षणवादी नीतियाँ, जैसे अनिवार्य डेटा स्थानीयकरण, वैश्विक स्केलेबिलिटी का लक्ष्य रखने वाले स्टार्टअप के लिये अनुपालन संबंधी बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।
 - उदाहरण के लिये, जबकि भारतीय स्टार्टअप कम्पनियाँ अनुपालन लागतों से जूझ रही हैं, वहीं अमेज़न जैसी वैश्विक प्रतिस्पर्धियों ने भारत में आक्रामक बाजार विस्तार जारी रखा है।

//



भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- **नियामक और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** नौकरशाही की अक्षमताओं को कम करने के लिये स्टार्टअप पंजीकरण, कराधान और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना महत्वपूर्ण है।

- एक एकीकृत, समयबद्ध एकल खड़िकी अनुमोदन प्रणाली वलिंब और अस्पष्टता को दूर कर सकती है।
- उदाहरण के लिये, व्यवसाय करने में आसानी के लिये सुधार 2.0 के दायरे का वसितार करने के साथ-साथ DPIIT की स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत अनुपालन लागत को कम करने से स्टार्टअप को सालाना सैकड़ों परचालन घंटे की बचत हो सकती है और तेज़ी से वसितार को बढ़ावा मलि सकता है।
- वतितपोषण तंत्र तक पहुँच का वसितार: भारत को कषेत्र-वशिषिट उद्यम नधिको बढ़ावा देना चाहयि और [स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स \(FFS\) कार्यक्रम](#) के दायरे को व्यापक बनाना चाहयि।
 - प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के लिये राजस्व-आधारित वतितपोषण जैसे नवीन वतितपोषण मॉडल को शुरू करने से इक्विटी कमज़ोर पड़ने का बोझ कम हो सकता है।
 - सडिबी स्टार्टअप फंड का वसितार करना तथा इसे हरति ऊर्जा और डीप-टेक जैसे उभरते कषेत्रों से जोड़ना, वतितपोषण संबंधी अंतराल को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है।
- शकिसा जगत और स्टार्टअप के बीच सहयोग बढ़ाना: संरचित उद्योग-अकादमिक सहयोग नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, वशिष रूप से डीप-टेक और बायोटेक स्टार्टअप में।
 - [नेशनल रसिर्च फाउंडेशन \(NRF\)](#) के तहत वशिषवदियालयों में नवाचार कषेत्र स्थापित करने से स्टार्टअप को अत्याधुनिक अनुसंधान और तकनीकी वशिषज्जता तक पहुँच प्रदान की जा सकती है।
 - इन कषेत्रों को अनुसंधान को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने तथा बौद्धिक संपदा केंद्रों के नरिमाण पर ध्यान केंद्रित करना चाहयि।
- ग्रामीण डजिटल अवसंरचना को मज़बूत करना: 100% ग्रामीण ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने के लिये भारतनेट कार्यक्रम का वसितार करना ग्रामीण स्टार्टअप पारसिथितिकी तंत्र को खोलने की कुंजी है।
 - कृषि प्रौद्योगिकी, एडटेक और ई-कॉमर्स कषेत्र में स्टार्टअप इंटरनेट की बढ़ती पहुँच के साथ फल-फूल सकते हैं।
 - सार्वजनिक-नजि भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत अंतमि-मिल कनेक्टविटी के लिये नजि अभकिर्त्ताओं के साथ साझेदारी करने से तेज़ी से क्रयानवयन सुनिश्चित हो सकता है और लागत कम हो सकती है, जिससे ग्रामीण समावेशता को बढ़ावा मलिगा।
- स्थरिता-केंद्रित स्टार्टअप को बढ़ावा देना: कर लाभ और सब्सडि के माध्यम से हरति स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने से पारसिथितिकी तंत्र भारत के जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित कया जा सकता है।
 - राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन और नवीकरणीय ऊर्जा सब्सडि जैसी स्थरिता पहलों को EVS, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं अपशिष्ट प्रबंधन में स्टार्टअप से जोड़ने से इस कषेत्र में नवाचार में तेज़ी आ सकती है।
 - उदाहरण के लिये, बैटरी रीसाइकलिंग स्टार्टअप के लिये अनुदान, पर्यावरणीय लक्ष्यों को स्टार्टअप विकास के साथ संरेखित कर सकता है।
- वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच में सुधार: सरकार समर्थित नरियात योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर वसितार करने के लिये प्रोत्साहित करने से उनके बाज़ार का आकार बढ़ सकता है।
 - अंतरराष्ट्रीय परदर्शनियों और व्यापार मशिनों में भागीदारी के लिये वतितपोषण को शामिल करने के लिये MADE (मैटरगि, एक्सेस, डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट) जैसे कार्यक्रम शुरू कये जाने चाहयि।
 - वैश्विक स्तर पर वाणजिय मंडलों के साथ साझेदारी करने से भारतीय स्टार्टअप को सीमा पार नेटवर्क बनाने में भी मदद मलि सकती है।
- उच्च ग्राहक अधगिरण लागत (CAC) से नपिटना: CAC को कम करने के लिये, सरकार [डजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क \(ONDC\)](#) जैसे डजिटल सार्वजनिक बुनयादी अवसंरचना को बढ़ावा दे सकती है ताकि समान अवसर उपलब्ध कराया जा सके।
 - ONDC छोटे स्टार्टअप को साझा संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम बना सकता है तथा भारी वपिणन व्यय पर नरिभरता कम कर सकता है।
 - इसके अतरिकित, ग्राहक प्रतधारण के लिये डेटा एनालटिक्स का लाभ उठाने वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने से ग्राहक कमी की दर कम हो सकती है, जिससे लाभप्रदता में सुधार हो सकता है।
- महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना: महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये लक्षित पहल, जैसे स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत तरजीही ऋण, लैंगिक असमानताओं को दूर कर सकते हैं।
 - वशिष रूप से महिला संस्थापकों के लिये मैटरशिप नेटवर्क का वसितार करना तथा सब्सडियुक्त सहकार्य स्थान उपलब्ध कराना, अधिक समावेशी स्टार्टअप वातावरण का नरिमाण कर सकता है।
- डजिटल सार्वजनिक वस्तुओं (DPG) का लाभ उठाना: स्टार्टअप स्केलेबल समाधान विकसित करने के लिये भारत के सुदृढ़ डजिटल बुनयादी अवसंरचना, जैसे डजिलिंकर का उपयोग कर सकते हैं।
 - स्टार्टअप के लिये इन प्लेटफॉर्मों पर ओपन-सोर्स API को बढ़ावा देने से नवाचार को बढ़ावा मलि सकता है।
 - उदाहरण के लिये, फनिटेक स्टार्टअप व्यक्तिगत वतित्तीय उत्पाद बनाने, बाज़ार में लाने के समय को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का उपयोग कर सकते हैं।
- मजबूत मैटरशिप नेटवर्क का नरिमाण: राष्ट्रीय और कषेत्रीय मैटरशिप नेटवर्क बनाने से संस्थापकों के बीच ज्ञान के अंतर को कम कया जा सकता है।
 - 'उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि (SAMRIDH)' कार्यक्रम के लिये MeitY के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर्स जैसे कार्यक्रमों को कषेत्र-वशिषिट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये वसितारित कया जा सकता है।
 - संरचित सरकारी नेतृत्व वाले कार्यक्रमों के माध्यम से सफल उद्यमियों को प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के साथ जोड़ने से उनकी अधगिम की प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है।
- गगि इकॉनमी स्टार्टअप को समर्थन देने के लिये श्रम कानूनों में सुधार: गगि और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को समायोजित करने के लिये श्रम सुधार पारसिथितिकी तंत्र की स्थरिता को बढ़ा सकते हैं।
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जैसे कार्यक्रमों के तहत गगि श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क और स्वास्थ्य लाभ का नरिमाण करके कार्यबल की अस्थरिता को कम कया जा सकता है।
 - इससे वशिष रूप से खाद्य वतिरण, राइड-हेलिंग और लॉजसि्टिक्स जैसे कषेत्रों के स्टार्टअप को लाभ होगा।
- उभरते कषेत्रों में सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देना: AI, ब्लॉकचेन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे कषेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने से

भारतीय स्टार्टअप वैश्विक नवाचार में अग्रणी स्थान पर आ सकते हैं।

- अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रमों पर केंद्रित द्विपक्षीय समझौते ज्ञान अंतरण को सक्षम कर सकते हैं।
- इन्हें स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के साथ एकीकृत करने से भारत की वैश्विक स्टार्टअप उपस्थिति बढ़ सकती है।

नष्िकर्ष:

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने सरकारी नीतियों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के वसितार और उभरते नविश परदृश्य के कारण उल्लेखनीय वृद्धि और वैश्विक क्षमता का प्रदर्शन किया है। हालाँकि, फंडिंग की कमी, नीतित अस्थिरता और प्रतभा प्रतधारण जैसी चुनौतियाँ महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं। इस इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिये, भारत को वनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थिति करना चाहिये ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना चाहिये और अकादमिक-स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देना चाहिये।

?????? ???? ????:

प्रश्न. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो गई है, फरि भी फंडिंग की कमी, वनियामक बाधाएँ और सीमति नवाचार जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. जोखमि पूँजी से क्या तातपर्य है? (2014)

- उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूँजी
- नये उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूँजी
- उद्योगों को हानि उठाने समय उपलब्ध कराई गई नधियाँ
- उद्योगों के प्रतसिथापन एवं नवीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई नधियाँ

उत्तर: (b)